नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 327
दि. 30.08.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

दलित सम्मान पर राहुल गांधी के आरोपों से गरमाई सियासत, भाजपा ने कांग्रेस के इतिहास पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। दलितों के सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राहुल गांधी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही दलित विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास और उसके भीतर दलित नेताओं के साथ कथित व्यवहार का हवाला देते हुए राहुल गांधी से सवाल किया कि जिस पार्टी पर वह दूसरों को दलित सम्मान का पाठ पढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, उसके अपने आचरण का रिकॉर्ड क्या रहा है।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और पार्टी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने अलग-अलग बयानों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास दलितों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार के दावों से मेल नहीं खाता। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के 'चाल, चरित्र और चेहरा' पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में दलित नेताओं को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके दावे सार्वजनिक मंचों पर किए जाते हैं।

गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस दलित सम्मान और सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ दलित नेता के सम्मान का सवाल आया तो पार्टी का व्यवहार अलग दिखाई दिया। पासवान ने वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद थे, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बाहर खड़े दिखाई दिए।

भाजपा प्रवक्ता ने इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस वास्तव में दलित सम्मान को लेकर इतनी गंभीर है तो पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे एक वरिष्ठ दलित नेता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों और राजनीतिक आरोपों के जरिए दलित सम्मान की बात करने से सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता साबित नहीं होती। इसके लिए राजनीतिक दलों के व्यवहार

और उनके आंतरिक आचरण को भी देखना होगा। पासवान ने पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समय राहुल गांधी की चप्पल उठाते हुए नारायणसामी की तस्वीर सामने आई थी। भाजपा नेता ने इसी तस्वीर का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि तस्वीरों को झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि इस आरोप का राजनीतिक अर्थ और संदर्भ कांग्रेस की ओर से अलग तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन भाजपा ने इसे राहुल गांधी के दलित सम्मान संबंधी बयानों के जवाब में प्रमुख मुद्दा बनाया है।

भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को दलितों के सम्मान के मुद्दे पर दूसरों को कटघरे में खड़ा करने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। उनका सवाल था कि कांग्रेस और राहुल गांधी को दलित सम्मान की चिंता केवल राजनीतिक बहस के दौरान ही क्यों होती है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस दलितों के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती रही है।

इसी क्रम में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ हुई कथित घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने राजस्थान में हरिश जाटव, योगेश जाटव और कृष्णा वाल्मीकि से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। त्रिवेदी ने पूछा कि जिन घटनाओं को लेकर भाजपा कांग्रेस से जवाब मांग रही है, उन घटनाओं के समय राज्य में किसकी सरकार थी और सरकार ने दलित समुदाय की सुरक्षा तथा न्याय के लिए क्या कदम उठाए। त्रिवेदी ने अपने बयान में कर्नाटक की एक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर पीएफआई से जुड़े लोगों द्वारा कथित हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने ही दलित विधायक का पर्याप्त साथ नहीं दिया। भाजपा सांसद के मुताबिक विधायक को न्याय की लड़ाई में अकेले संघर्ष करना पड़ा और बाद में उन्होंने निराश होकर पार्टी छोड़ दी।

भाजपा नेताओं के इन आरोपों का मूल तर्क यही है कि कांग्रेस यदि दलित सम्मान और सामाजिक न्याय को राजनीतिक मुद्दा बना रही है तो उसे अपने शासन वाले राज्यों और संगठन के भीतर दलित नेताओं के साथ हुए व्यवहार का भी जवाब देना चाहिए। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए कहा कि दलित समाज के हितों की बात केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

हालांकि, कांग्रेस और भाजपा के बीच दलित सम्मान का मुद्दा नया नहीं है। भारतीय राजनीति में दलित मतदाता लंबे समय से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति रहे हैं और लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल सामाजिक न्याय, समानता और दलित अधिकारों को लेकर अपनी-अपनी नीतियां और दावे पेश करते रहे हैं। ऐसे में जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाती है तो जवाब में उसके पुराने राजनीतिक फैसलों और नेताओं के साथ व्यवहार को सामने रखना भारतीय राजनीति में आम रणनीति रही है।

राहुल गांधी की राजनीति में भी सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की भागीदारी का मुद्दा लगातार प्रमुख रहा है। कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना, आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर समय-समय पर केंद्र सरकार और भाजपा पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। कांग्रेस का तर्क रहा है कि देश की संस्थाओं और सत्ता के ढांचे में पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदायों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। भाजपा इसके जवाब में कांग्रेस के शासन और राजनीतिक इतिहास का हवाला देकर उसके दावों पर सवाल उठाती रही है। मौजूदा विवाद भी इसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गया है।

एक तरफ राहुल गांधी दलितों के सम्मान और अधिकारों को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के भीतर दलित नेताओं की स्थिति को मुद्दा बना दिया है। इस राजनीतिक बहस में मल्लिकार्जुन खरगे का नाम विशेष रूप से सामने आया है, क्योंकि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ-साथ देश के प्रमुख दलित नेताओं में भी गिने जाते हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपने दलित नेताओं को संगठन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में किस प्रकार का सम्मान देती है। दूसरी ओर कांग्रेस की राजनीति में खरगे का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचना पार्टी के भीतर दलित प्रतिनिधित्व का उदाहरण माना जाता है। ऐसे में खरगे से जुड़े किसी भी सार्वजनिक घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण दोनों दल अपने-अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए करते हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के शासन पर सवाल उठाया और कहा कि दलितों के खिलाफ होने वाली कथित हिंसा के मामलों में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि राजनीतिक दलों को केवल विपक्षी दलों पर आरोप लगाने के बजाय अपने शासनकाल में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के रिकॉर्ड पर भी जवाब देना चाहिए।

भाजपा के आरोपों में कर्नाटक का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। अखंड श्रीनिवास मूर्ति से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने ही विधायक को पर्याप्त राजनीतिक और कानूनी समर्थन नहीं दिया। भाजपा ने इसे दलित नेताओं के साथ कांग्रेस के व्यवहार का उदाहरण बताया। हालांकि ऐसे राजनीतिक आरोपों में दोनों पक्षों के दावों और घटनाओं के पूरे संदर्भ को अलग-अलग देखना जरूरी है।

ताशकंद पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को नई दिशा देने पर होगी निर्णायक बातचीत

ताशकंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने स्वयं पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की मुलाकात ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल संपर्क और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा को मध्य एशिया में भारत की बढ़ती सक्रियता और क्षेत्रीय साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। आधुनिक दौर में दोनों देशों ने इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का रूप देते हुए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा का उद्देश्य इस साझेदारी को और व्यापक बनाना तथा भविष्य के सहयोग के लिए नए अवसर तलाशना माना जा रहा है।

ताशकंद पहुंचने पर राष्ट्रपति मिर्जियोयेव का स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचना दोनों देशों के बीच संबंधों की अहमियत को दर्शाता है। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की और बातचीत की। स्वागत के दौरान दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग की भावना दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि उज्बेकिस्तान की यह उनकी चौथी यात्रा है। उन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई और उनकी लगातार बढ़ती गति से जोड़ते हुए उज्बेकिस्तान के साथ भारत की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। भारत सरकार के स्तर पर भी इस यात्रा को मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है।

दोनों नेताओं के बीच होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान किए जाने की संभावना है। दोनों देश व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मौजूदा संभावनाओं को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

भारत के लिए उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। मध्य एशिया भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र पश्चिम एशिया, रूस, चीन और दक्षिण एशिया के बीच स्थित होने के कारण व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में उज्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना भारत की व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यापार और निवेश वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति देने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। भारत की फार्मास्युटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों की कंपनियों के लिए मध्य एशिया में संभावनाएं मौजूद हैं। वहीं उज्बेकिस्तान भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने में रुचि रखता है।

पाकिस्तान को लेकर भारत की रणनीति में आया बड़ा बदलाव ऑपरेशन सिंदूर ने दिया नया संदेश: पूर्व सेना प्रमुख नरवणे

वडोदरा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के प्रति भारत के सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया है। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई मुख्य रूप से सीमा के नजदीक मौजूद आतंकी ठिकानों तक सीमित रहती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई का दायरा पाकिस्तान के भीतर उन ठिकानों तक पहुंचा, जिन्हें आतंकवाद को समर्थन देने वाला माना गया। नरवणे के मुताबिक इस कार्रवाई से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने या उसका समर्थन करने वाले तत्व चाहे किसी भी स्थान पर मौजूद हों, वे भारतीय कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जा सकते।

वडोदरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में जनरल नरवणे ने भारत की पिछली सैन्य कार्रवाइयों और ऑपरेशन सिंदूर के बीच अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में सीमा के आसपास स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। बालाकोट में की गई कार्रवाई भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के भीतर मुरीदके और बहावलपुर जैसे स्थानों को निशाना बनाया, जिन्हें आतंकवाद से जुड़े ढांचे के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।

नरवणे ने कहा कि इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत की कार्रवाई की भौगोलिक सीमा से अधिक उसका रणनीतिक संदेश है। उनके मुताबिक भारत ने यह स्पष्ट किया कि केवल सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों

को अंजाम देने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले ढांचे को भी गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वालों के लिए अब यह मान लेना उचित नहीं होगा कि वे सीमा के दूसरी तरफ होने के कारण कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में किसी तरह की घबराहट नहीं दिखानी चाहिए। उनका कहना था कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में परिस्थितियों के अनुसार उचित समय पर उचित कार्रवाई करने की क्षमता भारत के पास है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सैन्य कार्रवाई का निर्णय परिस्थितियों, खुफिया सूचनाओं और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए नरवणे ने इसे भारत के सैन्य तौर-तरीकों में आए महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पेश किया। उनके मुताबिक भारत ने अपनी प्रतिक्रिया के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया कि आतंकवाद को केवल सीमा पार से होने वाली गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसके पूरे समर्थन तंत्र को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीरता से लिया जा सकता है।

उरी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। इन कार्रवाइयों ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में पहले ही बदलाव के संकेत दिए थे। नरवणे के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई के दायरे और संदेश दोनों में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित किया।

पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर भी पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का सैन्य मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। नरवणे ने भरोसा जताया कि भारत के पास अपनी सुरक्षा से जुड़े किसी भी खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता और आवश्यक संसाधन मौजूद हैं। उनके मुताबिक भारत को अपनी रक्षा क्षमता और रणनीतिक तैयारी पर विश्वास रखना चाहिए।

हालांकि भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में सैन्य क्षमता के अलावा कूटनीतिक और रणनीतिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दे तनाव का कारण रहे हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाइयों के साथ-साथ राजनयिक स्तर पर होने वाली गतिविधियां भी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

नरवणे ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा दोनों देशों के बीच जारी बातचीत पर भी अपनी राय रखी।

सीएनजी ने फिर बढ़ाया महंगाई का दबाव, 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी हुई गैस; ऑटो-टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में शनिवार से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई कीमत 29 अगस्त की सुबह छह बजे से लागू हो गई। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ईंधन की कीमत में अचानक हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर ऑटो, टैक्सी और अन्य सीएनजी वाहनों के संचालन पर पड़ने की आशंका है। वहीं ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग तेज करते हुए दिल्ली सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर 9 सितंबर को हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों को लेकर आम लोगों पर आर्थिक दबाव बना हुआ है। परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी महंगी होने से वाहन चालकों की परिचालन लागत बढ़ना तय माना जा रहा है। इसका असर केवल ऑटो और टैक्सी चालकों तक सीमित रहने के बजाय सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई की लागत पर भी पड़ सकता है।

ऑटो रिक्शा एसोसिएशन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महासचिव राजेंद्र सोनी ने सीएनजी की कीमत बढ़ाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने दिल्ली सरकार से एक सप्ताह के भीतर ऑटो और टैक्सी किराए में बढ़ोतरी करने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण चालकों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। वाहन चलाने के लिए ईंधन पर होने वाला खर्च बढ़ गया है, जबकि मौजूदा किराए में चालक अपनी लागत और परिवार का खर्च निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राजेंद्र सोनी के मुताबिक पिछले दो-तीन महीनों से सीएनजी की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार किराए में उचित बढ़ोतरी नहीं करती तो चालकों के सामने आर्थिक संकट और गहरा सकता है। यूनियन ने सरकार के सामने दो विकल्प रखे हैं—या तो ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की जाए या सीएनजी पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। यदि दोनों में से किसी मांग पर निर्णय नहीं लिया गया तो 9 सितंबर को हड़ताल का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी गई है।

सीएनजी की कीमत बढ़ने का असर परिवहन क्षेत्र के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि ईंधन की लागत में बढ़ोतरी का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। परिवहन के जरिए शहरों और राज्यों के बीच पहुंचने वाले सामान की लागत बढ़ने पर इसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

परिवहन लागत किसी भी वस्तु की अंतिम कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ट्रक, मालवाहक वाहन, टैक्सी या अन्य परिवहन साधनों का संचालन महंगा होता है तो कंपनियों और कारोबारियों की लागत बढ़ती है। यदि यह अतिरिक्त लागत लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर खाद्य पदार्थों, किराना सामान, औद्योगिक उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि सीएनजी के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर परिवहन क्षेत्र के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ी है।

आईजीएल की ओर से कीमत बढ़ाने का कारण गैस की बढ़ती लागत को बताया गया है। कंपनी के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वैश्विक बाजार में एलएनजी की कीमतों में तेजी आने का असर घरेलू गैस लागत पर पड़ा है। इसी बढ़ी हुई लागत को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए सीएनजी की कीमत में वृद्धि की गई है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर व्यापक रूप से पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस और एलएनजी की कीमतों में होने वाले बदलाव का प्रभाव उन देशों पर पड़ सकता है जो अपनी जरूरतों का एक हिस्सा आयात के जरिए पूरा करते हैं। भारत भी प्राकृतिक गैस और एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

डिजिटल अरेस्ट गिरोह का बड़ा खेल बेनकाब, 21 कंपनियां और 43 डमी निदेशक; 417 करोड़ की ठगी के नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा

नई दिल्ली। देशभर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक कथित संगठित नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। गोवा की एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.60 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ठगी के मामले की जांच करते हुए ईडी ने तीन और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने 27 अगस्त को भुषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार और शैलेश दगडू चव्हाण को गिरफ्तार किया। अदालत ने तीनों को एक सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में अब तक पांच आरोपित ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। ईडी की जांच में सामने आया कथित नेटवर्क केवल एक महिला को ठगने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैले होने का दावा किया गया है। एजेंसी के अनुसार इस नेटवर्क से जुड़ी 330 शिकायतें और 163 प्राथमिकी सामने आई हैं, जिनमें करीब 417.49 करोड़ रुपये की ठगी का पता चला है। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क में पैसे के प्रवाह, कंपनियों की भूमिका, बैंक खातों और कथित डमी निदेशकों के इस्तेमाल की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। मामला जून 2025 में दर्ज एक साइबर अपराध की प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप है कि गिरोह ने गोवा की एक महिला को वीडियो कॉल के माध्यम से अपने नियंत्रण में रखा। कथित तौर पर महिला को बताया गया कि वह एक आपराधिक मामले की जांच के घेरे में है और उसे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके बाद आरोपितों ने कथित रूप से डर और दबाव का माहौल बनाकर महिला से बड़ी रकम एक ऐसे खाते में ट्रांसफर करा ली, जिसे गुप्त निगरानी खाते के रूप में पेश किया गया था।

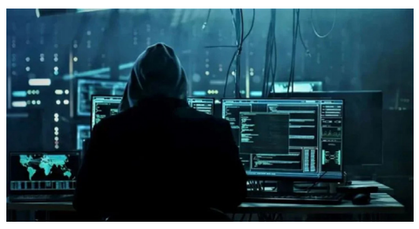

ईडी के अनुसार महिला से कुल 2 करोड़ 60 लाख 33 हजार 634 रुपये कथित तौर पर स्थानांतरित कराए गए। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी में अपराधी अक्सर खुद को पुलिस, जांच एजेंसी, अदालत या अन्य सरकारी संस्थानों का अधिकारी बताकर पीड़ित को भयभीत करते हैं। वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखने और गिरफ्तारी का डर दिखाने के बाद पीड़ित से बैंक खातों में पैसा भेजने के लिए कहा जाता है। इस मामले में भी जांच एजेंसी इसी तरह की कार्यप्रणाली की पड़ताल कर रही है।

ईडी की जांच में सबसे अहम कड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट भुषण सूर्यकांत मोये को बताया गया है। एजेंसी के मुताबिक मोये ने कथित तौर पर ठगी के पैसों को अलग-अलग माध्यमों से खपाने के लिए 21 कंपनियां खड़ी करने में मदद की। इन कंपनियों के संचालन के लिए 43 कथित डमी निदेशकों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन कंपनियों के बैंक खाते किस उद्देश्य से खोले गए, उनमें कितना पैसा आया और कितनी रकम आगे स्थानांतरित की गई। किसी संगठित साइबर ठगी के नेटवर्क में फर्जी या डमी कंपनियों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के लिए विशेष चिंता का विषय होता है। ऐसी कंपनियों के बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम को सामान्य कारोबारी लेन-देन के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा सकता है।

इसके बाद रकम को अलग-अलग खातों में भेजकर उसकी वास्तविक उत्पत्ति को छिपाने की कोशिश की जाती है। ईडी अब कथित तौर पर इसी पैटर्न को खंगाल रही है। एजेंसी के मुताबिक विलास नारायण पवार की भूमिका ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए आगे पहुंचाने में सामने आई है। उस पर कथित तौर पर आरटीजीएस के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में रकम स्थानांतरित करने का आरोप है। वहीं शैलेश दगडू चव्हाण पर इन बैंक लेन-देन के बदले कथित तौर पर नकदी उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी इन दोनों की भूमिका और नेटवर्क के अन्य सदस्यों से उनके संपर्क की भी जांच कर रही है।

ईडी ने 21 अगस्त को तीनों आरोपितों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसी के अनुसार तलाशी के दौरान सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि तलाशी कार्रवाई के बाद भी कथित तौर पर ठगी की रकम को खपाने का प्रयास जारी रहा। इसके बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ शुरू की गई।

417.49 करोड़ रुपये की कथित ठगी का आंकड़ा इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना देता है। ईडी के अनुसार नेटवर्क से जुड़ी शिकायतें और प्राथमिकी देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई हैं। इसका मतलब है कि गिरोह की गतिविधियां किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं थीं। अलग-अलग राज्यों में बैठे पीड़ितों को अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाया गया और कथित तौर पर ठगी की रकम को एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया।

जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को पहले अलग-अलग बैंक खातों में भेजा जाता था। इसके बाद कथित तौर पर उसे नकदी में बदला जाता था और फिर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किए जाने की व्यवस्था की जाती थी। इस तरह रकम को कई स्तरों से गुजारकर उसकी वास्तविक पहचान और स्रोत को छिपाने की कोशिश की जाती थी। ईडी अब इस कथित मनी ट्रेल को ट्रैक कर रही है ताकि नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी तकनीक और मनोवैज्ञानिक दबाव दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पीड़ित को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह किसी गंभीर आपराधिक मामले में फंस गया है। इसके बाद उसे वीडियो कॉल पर बने रहने, किसी से संपर्क न करने और निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। कई मामलों में अपराधी सरकारी वर्दी, फर्जी दस्तावेज और आधिकारिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर अपने दावे को विश्वसनीय बनाने की कोशिश करते हैं।

ऐसे मामलों में पीड़ित भय और मानसिक दबाव में आकर अपनी जमा पूंजी या परिवार की बचत तक अपराधियों को सौंप देते हैं। गोवा की महिला के मामले में भी जांच एजेंसी इसी तरह की कथित साजिश की जांच कर रही है। महिला से इतनी बड़ी रकम स्थानांतरित कराए जाने के बाद जब मामले की जानकारी सामने आई तो साइबर अपराध की प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच में धन के लेन-देन की कड़ियां ईडी तक पहुंचीं। इस मामले में अब तक पांच आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि जांच एजेंसी की कार्रवाई यहीं समाप्त होती नजर नहीं आ रही है। 21 कंपनियों और 43 कथित डमी निदेशकों की भूमिका सामने आने के बाद जांच का दायरा काफी बड़ा हो गया है।

संपादकीय

नौकरियों से जोड़ने वाली शिक्षा बने प्राथमिकता

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट हमारे नीति-निर्माताओं को आईना दिखाने वाली है। चौंकाने वाली ये रिपोर्ट बताती है कि देश में नब्बे फीसदी से अधिक स्नातक ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, जिसका उनकी डिग्री से कोई संबंध नहीं होता है। जाहिरा तौर पर यह आंकड़ा हमारी शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियों को ही उजागर करता है। इसके मायने हैं कि आज भी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है ,जो मौजूदा आर्थिकी से नहीं जोड़ती। देश-दुनिया का मौजूदा आर्थिक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। सरकारी नौकरियां ना के बराबर हैं, मगर हर स्नातक उसके लिये आवेदन करता है। जबकि रोजगार बाजार में उतरने के लिये युवाओं के पास कौशल विकास, व्यावहारिक दक्षता, तकनीकी ज्ञान और कुशल प्रबंधन का अनुभव होना जरूरी है। दरअसल, अधिकांश शिक्षण संस्थानों में आज भी वर्षों पुराना वह पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है जो मौजूदा प्रतिस्पर्धी समय में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं देता। इसके लिये जरूरी है कि युवाओं को उद्योग, बाजार व व्यावसायिक संस्थानों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा दी जाए। लेकिन विडंबना यह है कि तीन-चार साल के अध्ययन के बाद छात्रों को जो डिग्री मिलती है, वह उन्हें रोजगार के बाजार में कदमताल करने का हुनर नहीं देती। यह तभी संभव है जब हमारी शिक्षा, कौशल विकास व अर्थव्यवस्था में तारतम्य स्थापित हो सकेगा। लेकिन हर साल लाखों बीए, एम.ए. व अन्य मानविकीय विषयों की डिग्री हासिल करने वाले बेरोजगारों की पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि देश में स्नातक बेरोजगारों का प्रतिशत देश की सामान्य बेरोजगारी दर से कहीं अधिक है। महिला स्नातकों की दर तो पुरुष स्नातकों से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में उस उच्च शिक्षा का क्या औचित्य जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। असल में, बदलते वक्त के अनुरूप युवाओं की शिक्षा में जो जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए थे, वे अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाये हैं। दरअसल, हर युवा में कला-कौशल का एक विशिष्ट गुण होता है। उसका मूलभूत रुझान एक विशेष क्षेत्र में होता है। लेकिन इस गुण को न तो अभिभावक समझ पाते हैं और न ही शिक्षक। छात्र भेड़चाल में आकर शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते हैं। लेकिन यह उनकी रुचि का विषय नहीं होता है। कई अध्ययन बताते हैं कि अपनी रुचि के विषय में युवा बेहतर कार्य प्रदर्शन करते हैं। यह संभव नहीं कि हर छात्र डॉक्टर व इंजीनियर ही बने। लेकिन समाज में ऐसा करने की होड़ बनी हुई है। एक समय बैंकिंग, रेलवे आदि में भविष्य तलाशने की होड़ लगी। पिछले कुछ समय में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने का फैशन चला। वैश्विक स्थितियों में बदलाव व एआई के वर्चस्व के चलते अचानक कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में नौकरियों में तेजी से कटौती हुई। लेकिन देश में हजारों शिक्षण संस्थान आज भी इस भेड़चाल में युवाओं को धकेल रहे हैं। विडंबना यह है कि हमारे नीति-नियंताओं ने दूरदर्शी दृष्टिकोण न अपनाते हुए, भविष्य की दीवार पर लिखी इबारत को नहीं पढ़ा। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश होने के बावजूद हम इस जनसांख्यिकीय लाभ उठाने में विफल रहे हैं। हमारे उद्योगों ने भी अपनी जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये इस बाबत चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया। यही वजह है कि आज देश में कामचलाऊ इंटर्नशिप व अप्रेंटिसशिप का बोलबाला है। यदि हमारा निजी क्षेत्र इस दिशा में रचनात्मक पहल करता तो उसे बड़ी संख्या में अपनी जरूरतों के मुताबिक युवा प्रतिभाएं मिल सकती थीं। इसे दिशा देने में देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं आईआईटी व आईआईएम की बड़ी भूमिका हो सकती थी। याद रहे कि कौशल विकास का मतलब केवल एक सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है। देश को कौशल विकास से लैस युवाओं की जरूरत है। जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिये अनिवार्य शर्त भी है। नीति-नियंताओं को इस मामले में चीन की औद्योगिक व तकनीकी क्रांति से जुड़ी नीतियों से सीखने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे स्कूल-कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक में रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को तरजीह दी जाए।

भारत के हाथ आया Javelin हथियार, अब दुश्मनों के टैंकों की खैर नहीं! America से हुआ बड़ा रक्षा सौदा

"भारत के लिए यह जरूरत अचानक पैदा नहीं हुई है। भारतीय सेना करीब 2009 से ही आधुनिक तीसरी पीढ़ी की anti-tank guided missile प्रणाली की तलाश में रही है। जरूरत ऐसी मिसाइल की थी जो हल्की हो, सटीक हो और fire-and-forget क्षमता से लैस हो, ताकि पुरानी wire-guided प्रणालियों की सीमाओं से बाहर निकला जा सके।

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग अब सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रह गया है। भारतीय सेना द्वारा अमेरिकी Javelin एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए Letter of Offer and Acceptance (LOA) पर हस्ताक्षर इस बदलते रिश्ते का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अमेरिकी दूतावास ने इसे भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को अधिक गहरा, सक्षम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाला कदम बताया है। खास बात यह है कि इस समझौते के साथ भविष्य में दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सह-उत्पादन यानी co-production की संभावनाओं का रास्ता भी खुला है।Javelin की खासियत केवल यह नहीं है कि वह एक आधुनिक एंटी-टैंक मिसाइल है। यह एक man-portable, fire-and-forget प्रणाली है, यानी सैनिक मिसाइल दागने के बाद लक्ष्य पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए उसी स्थान पर मौजूद रहने को मजबूर नहीं होता। यही क्षमता युद्धक्षेत्र में सैनिकों की survivability बढ़ाती है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक Javelin भारी बख्तरबंद वाहनों के अलावा कई दूसरे battlefield targets को भी निशाना बना सकती है और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इस्तेमाल की जा सकती है। तेज engagement और उसके बाद तुरंत position बदलने की क्षमता इसे infantry के लिए खास तौर पर उपयोगी बनाती है।

इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: Kirana Hills और Skardu को लेकर पूर्व CDS Anil Chauhan के खुलासों से चौंकी दुनिया, Pakistan बात करना चाह रहा था, मगर India...

भारत के लिए यह जरूरत अचानक पैदा नहीं हुई है। भारतीय सेना करीब 2009 से ही आधुनिक तीसरी पीढ़ी की anti-tank guided missile प्रणाली की तलाश में रही है। जरूरत ऐसी मिसाइल की थी जो हल्की हो, सटीक हो और fire-and-forget क्षमता से लैस हो, ताकि पुरानी wire-guided प्रणालियों की सीमाओं से बाहर निकला जा सके। लेकिन तकनीक हस्तांतरण, लागत, खरीद प्रक्रिया और बाद में स्वदेशी विकास पर जोर जैसी वजहों से आधुनिक ATGM की तलाश लंबे समय तक खिंचती रही। यही वजह है कि Javelin का मौजूदा सौदा केवल एक और विदेशी हथियार खरीद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारतीय सेना की तत्काल operational जरूरत और दीर्घकालिक रक्षा औद्योगिक रणनीति के बीच एक पुल बन सकता है। अमेरिकी दूतावास ने साफ तौर पर कहा है कि LOA पर हस्ताक्षर के बाद भारत Javelin system का ग्राहक बन गया है और यह समझौता दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए दरवाजा खोलता है। यानी असली रणनीतिक महत्व मिसाइलों की संख्या से कहीं आगे है। देखा जाये तो इस सौदे का सामरिक महत्व भी बेहद स्पष्ट है। भारत को ऐसे युद्धक्षेत्र में अपनी infantry की anti-armour क्षमता मजबूत करनी है जहां बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया और सटीक प्रहार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Javelin की portability का अर्थ है कि इसे अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक अपेक्षाकृत लचीले ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। Fire-and-forget क्षमता सैनिक को launch के बाद तुरंत reposition करने की सुविधा देती है। ऐसे में missile केवल दुश्मन के armour को निशाना बनाने का साधन नहीं रहती, बल्कि छोटे infantry units की tactical flexibility बढ़ाने वाला हथियार बन जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों की दिशा का है। अमेरिकी राजदूत Sergio Gor ने कहा है कि यह समझौता अमेरिकी समर्थन की गहराई को दिखाता है और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करता है। वॉशिंगटन की नजर में भारत केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि भविष्य के defence industrial cooperation का साझेदार भी बन सकता है। अमेरिकी दूतावास ने दोनों देशों के defence industrial bases को मजबूत करने की संभावना पर विशेष जोर दिया है। देखा जाये तो यहीं से इस सौदे का रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। भारत एक ओर अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से आधुनिक बनाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यदि Javelin के क्षेत्र में co-production की संभावना वास्तविक औद्योगिक साझेदारी में बदलती है, तो भारत को केवल तैयार हथियार हासिल करने की बजाय अमेरिकी defence technology और manufacturing ecosystem के साथ अधिक गहरा जुड़ाव मिल सकता है। यह भारत के लिए लंबी अवधि में अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

हालांकि एक बात अभी साफ नहीं है कि भारत कितने Javelin systems खरीद रहा है और इस खरीद की कुल कीमत कितनी है। अमेरिकी दूतावास और रक्षा मंत्रालय ने इन विवरणों को सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए इस सौदे को तत्काल बड़े पैमाने की anti-tank क्षमता में बदलाव मानना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि भारत ने Javelin को अपने सैन्य विकल्पों में शामिल कर लिया है और साथ ही अमेरिका के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग का एक और दरवाजा खोल दिया है।

बहरहाल, Javelin सौदे का संदेश दो स्तरों पर है। युद्धक्षेत्र के लिए भारत अपनी infantry को ज्यादा सटीक, मोबाइल और survivable anti-armour क्षमता देना चाहता है; और रणनीतिक स्तर पर वॉशिंगटन के साथ रक्षा संबंध को खरीददार-विक्रेता के रिश्ते से आगे ले जाना चाहता है। अगर co-production की बात जमीन पर उतरती है, तो यही सौदा आने वाले वर्षों में भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के अगले चरण की शुरुआत साबित हो सकता है।

प्रेरणा

खाली मन ही सीख सकता है जीवन का सबसे बड़ा सत्य

एथेंस की संकरी गलियों में एक दिन महान दार्शनिक सुकरात हमेशा की तरह शांत भाव से टहल रहे थे। उनके आसपास लोगों की भीड़ थी, लेकिन सुकरात अपने विचारों में खोए हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी सादगी थी, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वे ज्ञान की बातें करते थे, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे और जीवन के कठिन विषयों पर संवाद करते थे। इसके बावजूद वे स्वयं को कभी सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं मानते थे।

एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह पढ़ा-लिखा था और अपनी बुद्धिमत्ता पर उसे बहुत गर्व था। उसने सुकरात से कहा, "मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको महान बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन मैं आपकी एक बात को समझ नहीं पाता। यदि आप इतने ज्ञानी हैं, तो फिर बार-बार यह क्यों कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते?"

सुकरात ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद उन्होंने युवक से पूछा, "तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है? क्या तुम बहुत कुछ जानते हो?"

युवक ने बिना देर किए कहा, "हां, मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैंने अनेक किताबें पढ़ी हैं। इतिहास, राजनीति, दर्शन और गणित का अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि ज्ञान के मामले में मैं अपने आसपास के बहुत से लोगों से आगे हूं।"

सुकरात ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर वे उसे अपने साथ लेकर थोड़ी दूर चले। रास्ते में उन्हें मिट्टी का एक बड़ा घड़ा दिखाई दिया। सुकरात उस घड़े के पास रुके और युवक से बोले, "मान लो यह घड़ा पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। क्या इसमें तुम एक बूंद और पानी डाल सकते हो?"

युवक ने कहा, "नहीं, यदि घड़ा पूरी तरह भर चुका है तो उसमें और पानी डालने की जगह नहीं होगी। पानी डालने पर वह बाहर गिर जाएगा।"

सुकरात ने कहा, "मनुष्य का मन भी इसी घड़े की तरह है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, तब उसके भीतर नई बातों के लिए जगह समाप्त हो जाती है। वह दूसरों की बात सुनता जरूर है, लेकिन सीखने के लिए नहीं। वह केवल यह देखने के लिए सुनता है कि सामने वाला उसकी जानकारी से सहमत है या नहीं।"

युवक पहली बार गंभीर हुआ। उसे लगा कि सुकरात की बात सीधे उसके अहंकार पर चोट कर रही है।

सुकरात ने आगे कहा, "मैं स्वयं को अज्ञानी इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं अपनी सीमाओं को पहचानता हूं। मुझे पता है कि संसार बहुत विशाल है और मेरा ज्ञान बहुत छोटा। जितना अधिक मैं जानने की कोशिश करता हूं, उतना ही मुझे महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।"

युवक ने पूछा, "लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने बहुत अध्ययन किया हो और उसके पास बहुत ज्ञान हो, तो क्या उसे अपने ज्ञान पर गर्व नहीं होना चाहिए?"

सुकरात बोले, "ज्ञान पर संतोष होना गलत नहीं है, लेकिन ज्ञान का अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। वास्तविक ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है, वह जानता है कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसी बात हो सकती है, जिसे वह स्वयं नहीं जानता।"

युवक अब बिल्कुल शांत था। सुकरात ने उसकी ओर देखते हुए कहा, "कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर कहे कि मैंने नदी को समझ लिया है। क्या केवल नदी को देखकर वह उसके पूरे प्रवाह, उसकी गहराई और उसके भीतर छिपी दुनिया को जान सकता है? संसार भी इसी नदी की तरह है। हम उसका थोड़ा-सा हिस्सा देखते हैं और फिर सोच लेते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया।"

इन शब्दों ने युवक को भीतर तक प्रभावित किया। उसे अपने व्यवहार की कई बातें याद आने लगीं। वह अक्सर दूसरों की बात बीच में रोक देता था। उसे अपनी राय सबसे सही लगती थी। जब कोई उसे कोई नई बात बताता, तो वह उसे स्वीकार करने के बजाय अपनी जानकारी दिखाने लगता था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका ज्ञान उसे आगे बढ़ाने के बजाय कई बार उसके रास्ते में दीवार बन गया था।

उसने सुकरात से कहा, "आज मुझे समझ में आया कि मेरी सबसे बड़ी कमी यह नहीं है कि मैं कम जानता हूं, बल्कि यह है कि मैं यह मानता रहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं।"

सुकरात मुस्कुराए और बोले, "यही समझ ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मनुष्य जब अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर सीखने की सच्ची इच्छा पैदा होती है।"

युवक ने पूछा, "तो क्या बुद्धिमान बनने के लिए हमेशा यह स्वीकार करते रहना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते?"

सुकरात ने कहा, "हां। क्योंकि सीखना किसी एक उम्र, एक किताब या एक शिक्षक तक सीमित नहीं है। जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी कोई बच्चा हमें सरलता सिखा देता है, कभी कोई बुजुर्ग धैर्य का अर्थ समझा देता है, कभी कोई असफलता हमें ऐसी शिक्षा दे जाती है, जो वर्षों की सफलता भी नहीं दे सकती।"

युवक ने सिर झुका लिया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा गर्व नहीं था। उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। वह जान गया था कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि ज्ञान की पहचान है।

हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम अपनी उपलब्धियों पर अत्यधिक गर्व करने लगते हैं, तो सीखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी सोच ही सही है, हमारा अनुभव ही अंतिम सत्य है और हमारी राय से बेहतर कोई राय नहीं हो सकती। लेकिन यही सोच धीरे-धीरे हमारे विकास को रोक देती है।

इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह गलती होने पर उसे स्वीकार करता है, दूसरों की सलाह सुनता है और अपने विचारों को बदलने में संकोच नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि किसी से सीखने का अर्थ छोटा होना है। वह समझता है कि सीखने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता।ुकरात की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ साबित होना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है, उसके भीतर आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार को ही अपनी पहचान बना लेता है, उसके लिए सीखने के सभी दरवाजे धीरे-धीरे बंद हो जाते हैं।

भागवत की न्यूयॉर्क यात्रा: आर्थिक निवेश, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक संघ नेटवर्क का विस्तार

इस पूरी यात्रा का सबसे पहला और आर्थिक रूप से अत्यंत व्यावहारिक पड़ाव न्यूयॉर्क में वैश्विक कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों, नीति-निर्माताओं और उद्यम पूंजीपतियों के साथ आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक थी । इस संवाद के दौरान पारंपरिक द्विपक्षीय व्यापार के स्थापित ढांचों से आगे बढ़कर पूरी तरह से भविष्य की उन्नत प्रौद्योगिकियों यानी डीप-टेक पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस उच्च-स्तरीय बैठक में दूरसंचार क्षेत्र के आधुनिकीकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी निवेश की संभावनाओं, स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक लक्ष्यों और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक विधाओं में भारत-अमेरिका के बीच सहयोग पर गहराई से विमर्श हुआ। डॉ. मोहन भागवत ने वैश्विक निवेशकों के सामने भारत को एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक, कानून सम्मत और विकासोन्मुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूती से प्रस्तुत किया। इस चर्चा के दौरान अमेरिकी निवेशकों ने भारत के विशाल बाजार और उसकी बढ़ती आर्थिक क्षमता की सराहना तो की, लेकिन साथ ही उन्होंने राज्य स्तर पर आने वाली प्रशासनिक और विनियामक बाधाओं पर अपनी व्यावहारिक चिंताएं भी साझा कीं। निवेशकों का मुख्य तर्क यह था कि यदि भारत को चीन के एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में आना है, तो भूमि अधिग्रहण, जटिल कर संरचनाओं और स्थानीय स्तर पर फैक्ट्रियां स्थापित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाना होगा, ताकि प्रशासनिक देरी के बिना निवेश धरातल पर उतर सके। इसी बैठक में सिलिकॉन वैली की जानी-मानी निवेश भागीदार आशा जडेजा मोटवानी जैसी हस्तियों ने भागवत के इस विचार का पुरजोर समर्थन किया कि भारत की युवा जनसांख्यिकी आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और भारतीय युवा न केवल अपने देश के विकास के इंजन हैं बल्कि वे पूरी दुनिया में सकारात्मक और तकनीकी बदलावों के सबसे बड़े संवाहक बनकर उभर रहे हैं ।

इसे भी पढ़ें: USCIRF बनाम RSS: आरोप, अधिकार-सीमा और भारत-अमेरिका संबंधों की अग्निपरीक्षा

इस तीन दिवसीय दौरे का दूसरा और दृश्य रूप से सबसे भव्य पहलू न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक और दुनिया भर में प्रसिद्ध मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाला 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' है । रक्षाबंधन के पावन सांस्कृतिक अवसर पर आयोजित होने वाले इस विशाल समागम में पूरे अमेरिका महाद्वीप से 5,000 से अधिक विशिष्ट भारतीय प्रवासियों और सैकड़ों सांस्कृतिक, दार्शनिक व आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई । इस भव्य आयोजन के पीछे बहुत गहरे भू-राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ छिपे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे उत्सव का मूल दर्शन भारतीय संस्कृति के कालजयी विचार 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, के सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे दौर में जब पूरा विश्व भू-राजनीतिक संघर्षों, युद्धों, वैचारिक ध्रुवीकरण और गंभीर जलवायु संकटों से जूझ रहा है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे अत्यधिक प्रभावशाली पश्चिमी मंच से सर्वसमावेशी, बहुसांस्कृतिक और अंतरधार्मिक एकता का संदेश देना भारत की उस 'विश्व-मित्र' वाली छवि को वैश्विक जनमानस में स्थापित करता है जो सभी के कल्याण की कामना करती है। यह आयोजन अमेरिकी समाज, वहां की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और राजनीति में शीर्ष पदों पर आसीन भारतीय प्रवासियों की एकजुटता और उनकी जनसांख्यिकीय व आर्थिक शक्ति का भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है , जिसकी उपेक्षा कोई भी अमेरिकी सरकार या नीति-निर्माता नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के माध्यम से संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाफ बने पुराने नैरेटिव को तोड़ने और पश्चिमी दुनिया के सामने खुद को एक वैश्विक, समावेशी और परोपकारी दार्शनिक आंदोलन के रूप में पेश करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।

इस ऐतिहासिक यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी आयाम प्रवासी भारतीयों के बीच संघ की अंतरराष्ट्रीय शाखाओं, विशेष रूप से हिंदू स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर पड़ने वाला प्रभाव है। डॉ. भागवत की इस उपस्थिति ने अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में सक्रिय एचएसएस के नेटवर्क को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है। भारत से बाहर रहने वाले हिंदुओं को अपनी संस्कृति, जड़ों और मूल्यों से जोड़े रखने में हिंदू स्वयंसेवक संघ दशकों से मूक भाव से काम कर रहा है, लेकिन इस स्तर के शीर्ष नेतृत्व के प्रवास ने इन गतिविधियों को मुख्यधारा की वैश्विक चर्चा में ला खड़ा किया है। इस यात्रा के बाद विदेशों में चल रही संघ की साप्ताहिक और मासिक 'बालगोकुलम' जैसी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है, जहां प्रवासी परिवारों की नई पीढ़ी को भारतीय दर्शन, योग और नेतृत्व क्षमता के संस्कार दिए जाते हैं। एचएसएस के माध्यम से प्रवासी भारतीय केवल सांस्कृतिक रूप से ही संगठित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे अमेरिकी समाज में परोपकार, आपदा प्रबंधन और स्थानीय सामुदायिक सेवा के कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। संघ प्रमुख ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विदेशों में रहने वाले स्वयंसेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी कर्मभूमि (अमेरिका) के प्रति पूरी तरह वफादार और अनुशासित रहते हुए अपनी मातृभूमि (भारत) के सांस्कृतिक गौरव को अक्षुण्ण रखें।

अभियान

पुष्कर की पहाड़ियों में विराजती हैं मां शक्ति, जानिए मणिवेदिका शक्तिपीठ की अनसुनी कथा

राजस्थान की धरती केवल अपने किलों, महलों, रेगिस्तान और राजपूत वीरता की कहानियों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह भूमि अनेक प्राचीन धार्मिक स्थलों और पौराणिक रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। इन्हीं पवित्र स्थलों में राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर का नाम विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भगवान ब्रह्मा के प्रसिद्ध मंदिर और पवित्र पुष्कर सरोवर के कारण दुनिया भर में पहचान रखने वाला पुष्कर अपने भीतर देवी उपासना की एक ऐसी परंपरा भी समेटे हुए है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुष्कर की पुरूहोता पहाड़ी क्षेत्र में राजराजेश्वरी मणिवेदिका शक्तिपीठ स्थित है, जिसे कई परंपराओं में 27वां शक्तिपीठ माना जाता है।

पुष्कर का नाम आते ही श्रद्धालुओं के मन में सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर सरोवर और सावित्री माता की पहाड़ी की छवि उभरती है। लेकिन इन्हीं धार्मिक स्थलों के आसपास ऐसी मान्यताएं भी जीवित हैं, जो सदियों से भक्तों को आकर्षित करती रही हैं। पुरूहोता पर्वत की तलहटी में स्थित मणिवेदिका शक्तिपीठ को ऐसी ही एक प्राचीन शक्ति-स्थली माना जाता है। स्थानीय धार्मिक परंपराओं में इसे मां आदिशक्ति का पवित्र धाम बताया गया है। यहां देवी को राजराजेश्वरी मणिवेदिका के रूप में पूजा जाता है, जबकि स्थानीय लोग मां को चामुंडा माता के नाम से भी जानते हैं।

शक्तिपीठों की परंपरा मां सती की उस महान कथा से जुड़ी है, जिसमें भगवान शिव, माता सती और राजा दक्ष का प्रसंग आता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। भगवान शिव का वैरागी स्वरूप, उनका साधारण जीवन और देवताओं से अलग व्यक्तित्व दक्ष को पसंद नहीं था। दूसरी ओर उनकी पुत्री सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति नाराजगी कम नहीं हुई। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने अनेक देवी-देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को अपने पिता के यहां होने वाले यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में पिता के घर जाने की इच्छा हुई।

माता सती ने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मानपूर्वक निमंत्रण न दिया गया हो, वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन पुत्री का अपने पिता के घर जाने का भाव इतना प्रबल था कि माता सती यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। वह अपने पिता के घर पहुंचीं, लेकिन वहां उनका स्वागत उस प्रेम और सम्मान के साथ नहीं हुआ, जिसकी उन्हें अपेक्षा थी।

यज्ञ स्थल पर माता सती ने देखा कि सभी देवी-देवताओं के लिए स्थान निर्धारित था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं रखा गया था। जब उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव के प्रति ऐसी उपेक्षा का कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सुनकर माता सती अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं।

माता सती ने महसूस किया कि जिस देह के कारण उन्हें दक्ष की पुत्री होने का संबंध मिला है, उसी देह के सामने उनके आराध्य पति का अपमान हो रहा है। उन्होंने यज्ञ की अग्नि के सामने संकल्प लिया और अपनी देह का त्याग कर दिया। माता सती के देहत्याग की खबर जब भगवान शिव तक पहुंची तो उनका क्रोध और दुख पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था।

भगवान शिव माता सती की देह को अपने कंधे पर लेकर रौद्र रूप में ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनकी वेदना और क्रोध के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के विभिन्न अंग और आभूषण धरती पर अलग-अलग स्थानों पर गिरे। जिन स्थानों पर माता सती के अंग या उनसे जुड़े पवित्र अवशेष गिरे, वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ के रूप में पूजित हुए। इन्हीं शक्तिपीठों की परंपरा में पुष्कर के पुरूहोता पर्वत का नाम भी आता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां माता सती के दोनों हाथों के मणिबंध यानी कलाइयां गिरी थीं। इसी वजह से इस स्थान को मणिवेदिका शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि माता के मणिबंध के धरती पर गिरने से इस पर्वतीय क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ गई।

पुरूहोता पर्वत को लेकर स्थानीय परंपराओं में एक और रोचक कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर माता सती के मणिबंध गिरे, वहां धरती में एक विशाल गड्ढा बन गया था। यह स्थान पहाड़ी के बीच और दुर्गम क्षेत्र में बताया जाता है। प्राकृतिक रूप से कठिन रास्ते के कारण यहां सामान्य धार्मिक स्थलों की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच नहीं पाते थे। इसी वजह से यह शक्तिस्थल लंबे समय तक आम लोगों की जानकारी से दूर रहा।

स्थानीय मान्यता में एक वृद्ध महिला भक्त की कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि वह मां शक्ति की अनन्य भक्त थी और नियमित रूप से देवी की आराधना करती थी। उम्र बढ़ने के साथ उसके लिए पहाड़ी के दुर्गम स्थान तक पहुंचना कठिन हो गया। उसने मां से प्रार्थना की कि यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो मां उसे अपने दर्शन ऐसी जगह दें, जहां वह आसानी से पहुंच सके। भक्त की पुकार सुनकर मां उसके समीप आ गईं—ऐसी स्थानीय आस्था है। माना जाता है कि देवी ने पहाड़ के अत्यंत दुर्गम हिस्से से नीचे तलहटी की ओर अपना स्थान बनाया, ताकि उनकी वृद्ध भक्त भी दर्शन और पूजा कर सके। इसी लोकविश्वास ने इस स्थान को भक्तों के लिए और अधिक भावनात्मक बना दिया।

यह कथा केवल आस्था की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भारतीय धार्मिक परंपरा को भी दर्शाती है जिसमें देवी को भक्त के प्रेम और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। भक्त और भगवान के बीच संबंध केवल मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि सच्ची पुकार को देवी तक पहुंचने वाला माध्यम माना जाता है। पुष्कर की इस शक्ति-स्थली से मां गायत्री की उपासना की परंपरा भी जुड़ी हुई बताई जाती है। यहां आदिशक्ति और गायत्री के स्वरूप को साथ जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। स्थानीय लोग मां को चामुंडा माता के नाम से भी श्रद्धा से पुकारते हैं।

पुष्कर स्वयं भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की नगरी माना जाता है। यहां स्थित पुष्कर सरोवर के बारे में भी अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए पहुंचते हैं। इसी धार्मिक वातावरण के बीच पुरूहोता पर्वत की शक्ति-परंपरा पुष्कर को देवी उपासना की दृष्टि से भी विशेष बनाती है।

शक्तिपीठों को लेकर अलग-अलग धार्मिक ग्रंथों और क्षेत्रीय परंपराओं में संख्या और स्थानों को लेकर मतभेद भी मिलते हैं। कहीं 51, कहीं 52 और कहीं अन्य संख्या में शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अलग-अलग परंपराओं में शक्तिपीठों से जुड़े अंगों और देवी-भैरव के स्वरूपों का वर्णन भी अलग-अलग मिलता है। इसलिए पुष्कर के मणिवेदिका शक्तिपीठ को 27वां शक्तिपीठ मानने की बात को स्थानीय और विशिष्ट धार्मिक परंपरा के संदर्भ में समझना उचित है। स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक साहित्य में पुष्कर का विशेष महत्व बताया गया है। पुष्कर को तीर्थराज की संज्ञा भी दी जाती है। यहां ब्रह्मा जी की पूजा, सरोवर की महिमा और आसपास के अनेक धार्मिक स्थलों का वर्णन मिलता है। इसी व्यापक तीर्थ परंपरा के कारण पुष्कर केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।

मणिवेदिका शक्तिपीठ की विशेषता यह भी है कि यह स्थान प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों की भीड़ से कुछ अलग दिखाई देता है। बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों की तुलना में इस शक्तिस्थल के बारे में सामान्य श्रद्धालुओं को कम जानकारी है। यही कारण है कि यहां की धार्मिक मान्यता और स्थानीय कथाएं अभी भी अपेक्षाकृत सीमित दायरे में ही चर्चित हैं। पुरूहोता पहाड़ी की प्राकृतिक बनावट और आसपास का शांत वातावरण इस स्थान को और रहस्यमय बना देता है। पहाड़ियों के बीच देवी की शक्ति की कल्पना भक्तों के मन में एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति पैदा करती है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु केवल देवी के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि उस प्राचीन कथा को भी याद करते हैं, जिसने भारतीय धार्मिक परंपरा में शक्ति उपासना को एक विशेष स्थान दिया।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

नेपाल की बाढ़ ने बढ़ाई चिंता, 11 देशों के 753 लोग लापता; 183 भारतीयों की तलाश में जुटीं टीमें

काठमांडू। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। नेपाल पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 753 लोग अब तक लापता बताए गए हैं। इनमें 183 भारतीय नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में नेपाल के अलावा भारत, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूक्रेन, सिंगापुर और रूस सहित कई देशों के नागरिक शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना ने नेपाल के साथ-साथ उनके परिवारों की चिंता भी बढ़ा दी है।

रसुवा क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ ने कई स्थानों पर भारी तबाही मचाई है। तेज पानी और मलबे के बहाव के कारण सड़क मार्ग, पुल और अन्य संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई इलाकों में लोगों तक पहुंचना बचाव दलों के लिए चुनौती बना हुआ है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लगातार खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। लापता लोगों की जानकारी जुटाने के साथ-साथ संभावित प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज किया गया है।

नेपाल पर्यटन विभाग की सूची के अनुसार 753 लापता लोगों में 385 पुरुष और 337 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 31 लोगों का लिंग सूची में दर्ज नहीं किया गया है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में 164 नेपाली नागरिक भी लापता बताए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि आपदा का असर केवल विदेशी पर्यटकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आए हैं।

रसुवा नेपाल का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक तथा धार्मिक यात्रियों का आना-जाना रहता है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में अचानक आई बाढ़ और मलबे के बहाव ने राहत एवं बचाव कार्य को और कठिन बना दिया है। कई स्थानों तक पहुंचने के लिए बचाव दलों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

लापता लोगों की सूची में सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की बताई गई है। कुल 183 भारतीयों के लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद भारत में भी उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए भारतीय अधिकारियों की ओर से नेपाल सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखा जा रहा है। राहत एवं बचाव अभियान में भारत की ओर से भी अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

नेपाल में राहत अभियान के बीच शनिवार को रसुवा की एक पनबिजली परियोजना से चार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाए जाने की खबर सामने आई। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और उन्हें जल्द काठमांडू लाए जाने की उम्मीद है। इन नागरिकों के सुरक्षित बचने से राहत मिली है, लेकिन 183 भारतीयों के अब भी लापता होने की जानकारी के कारण खोज अभियान को लेकर दबाव बना हुआ है।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान के लिए नेपाल पुलिस, प्रशासन तथा अन्य संबंधित एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि लापता लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाए और उनके संभावित ठिकानों की पहचान कर वहां तलाशी अभियान चलाया जाए। आपदा के बाद संपर्क व्यवस्था बाधित होने के कारण कई लोगों की सही स्थिति का पता लगाने में समय लग रहा है।

इस बीच लापता और मृत लोगों की पहचान में मदद के लिए भारत ने भी विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई है। छह सदस्यीय फोरेंसिक विशेषज्ञ दल शनिवार को काठमांडू पहुंचा। इस दल का उद्देश्य डीएनए जांच और अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन लोगों की पहचान में सहायता करना है, जिनकी पहचान सामान्य तरीकों से संभव नहीं हो पा रही है।

बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के बाद मृतकों और लापता लोगों की पहचान करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में शामिल होता है। बाढ़ और मलबे के कारण शवों की पहचान मुश्किल हो सकती है। ऐसी स्थिति में डीएनए जांच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत से भेजी गई फोरेंसिक टीम नेपाल के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर पहचान प्रक्रिया में सहायता कर सकती है।

भारत की ओर से एक अन्य तकनीकी दल भी नेपाल पहुंच चुका है। यह दल सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में तकनीकी सहायता दे रहा है। रसुवा क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के कारण कई स्थानों पर सुरंगें और भूमिगत संरचनाएं मौजूद हैं। बाढ़ और मलबे के बाद इन स्थानों पर फंसे लोगों तक पहुंचना बचाव दलों के लिए कठिन हो सकता है।

सुरंगों में बचाव अभियान के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता और उपकरणों की जरूरत होती है। सीमित जगह, पानी, मलबे और कमजोर ढांचे के बीच काम करना जोखिम भरा होता है। भारतीय तकनीकी दल की मौजूदगी से स्थानीय बचाव एजेंसियों को अतिरिक्त विशेषज्ञता और संसाधन मिल सकते हैं। इसका उद्देश्य फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना है।

नेपाल में आई इस आपदा का असर कई देशों के नागरिकों पर पड़ा है। पर्यटन विभाग की सूची में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूक्रेन, सिंगापुर और रूस समेत कई देशों के नागरिकों के नाम शामिल हैं। इससे यह भी पता चलता है कि रसुवा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही कितनी महत्वपूर्ण है।

विदेशी नागरिकों के लापता होने के कारण नेपाल सरकार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राहत एवं बचाव अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। विभिन्न देशों के दूतावास और संबंधित अधिकारी अपने नागरिकों की जानकारी हासिल करने के लिए नेपाली अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रभावित लोगों के परिवारों को लगातार जानकारी उपलब्ध कराना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।

प्राकृतिक आपदा के बाद सबसे बड़ी मुश्किल संचार और संपर्क व्यवस्था को लेकर होती है। जिन क्षेत्रों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहां राहत दलों की पहुंच सीमित हो जाती है। कई बार मोबाइल नेटवर्क और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के लापता होने या सुरक्षित होने की सूचना परिवार तक पहुंचने में देरी हो सकती है।

रसुवा जैसे पहाड़ी इलाके में यह चुनौती और गंभीर हो जाती है। संकरी घाटियां, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्ते राहत दलों की गति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में भारी मलबा जमा हो जाए तो वहां तक पहुंचने के लिए विशेष मशीनरी और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी वजह से नेपाल के साथ भारत और अन्य सहयोगी एजेंसियों की विशेषज्ञ सहायता महत्वपूर्ण हो जाती है।

लापता लोगों की संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में खोज अभियान का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। बचाव दल संभावित प्रभावित स्थानों, नदी के किनारों, मलबे से भरे क्षेत्रों, परियोजना स्थलों और संपर्क मार्गों के आसपास तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों से भी लापता लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

चार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाए जाने की घटना ने बचाव अभियान में उम्मीद जरूर जगाई है। इससे यह संभावना भी मजबूत हुई है कि कुछ अन्य लापता लोग कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में अधिकारियों के लिए हर संभावित स्थान की जांच करना और खोज अभियान को लगातार जारी रखना बेहद जरूरी है।

भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से मजबूत सामाजिक और मानवीय संबंध रहे हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच लगातार आवाजाही होती है। बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक नेपाल जाते हैं और नेपाली नागरिक भारत में रोजगार, व्यापार तथा अन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। इसलिए नेपाल में आई किसी बड़ी आपदा का असर दोनों देशों के लोगों पर पड़ता है।

ऐसी स्थिति में भारत की ओर से फोरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी बचाव दल को भेजना केवल राहत सहायता नहीं बल्कि मानवीय सहयोग का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे नेपाल को आपदा के बाद मृतकों और लापता लोगों की पहचान तथा कठिन बचाव अभियानों में मदद मिल सकती है।

फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता 753 लापता लोगों का पता लगाना है। इनमें 183 भारतीय नागरिकों के अलावा कई अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने चुनौती है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खोज एवं बचाव अभियान को तेज किया जाए और परिवारों तक सही एवं प्रमाणित जानकारी पहुंचाई जाए।

भारत की ओर से भेजी गई छह सदस्यीय फोरेंसिक टीम और तकनीकी बचाव दल से अभियान को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं चार भारतीय नागरिकों के सुरक्षित बचाए जाने से राहत मिली है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं, इसलिए अभियान को लेकर सतर्कता और प्रयास दोनों बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है।

नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर यह दिखाया है कि हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं कितनी व्यापक चुनौती पैदा कर सकती हैं। ऐसे इलाकों में बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन की तैयारी, मजबूत संपर्क व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता लगातार बनी रहती है।

31 अगस्त 2026 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) 2027 के कर्टन रेज़र कार्यक्रम का भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन

गांधीनगर : माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में अमेरिका और कनाडा के उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के सफल दौरे के बाद गुजरात सरकार द्वारा 31 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) 2027 का कर्टन रेज़र कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कर्टन रेज़र आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए प्रभावी मंच तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि आगामी VGGS का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल एवं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ संवाद सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं, शाम को होटल ताज पैलेस में मिशन प्रमुखों एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित संवाद सत्र को भी संबोधित करेंगे।

भारत मंडपम में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल विभिन्न प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ वन-ऑन-वन बैठकें करेंगे।

इन कंपनियों में टीपीआरईएल, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, सियोल सेमीकंडक्टर्स, श्री सीमेंट लिमिटेड, पुरवाह ग्रीन पावर, एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस, जेबीएम ग्रुप, दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन, मैक्स हेल्थकेयर, यूनो मिंडा एवं एसीएमए, एसीएमई सोलर, श्विहाग एजी, एयरट्रंक, एचआईएफ ग्लोबल, जीएचसीएल, एसबर बैंक, पीबी फिनटेक लिमिटेड (पॉलिसीबाज़ार एवं पैसा बाज़ार की मूल कंपनी) तथा मैनकाइंड फार्मा शामिल हैं।

इन वन-ऑन-वन बैठकों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य एवं फार्मा, रेलवे, एआई एवं डेटा सेंटर, आईटी एवं बीपीएम, रसायन तथा बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI) जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बैठकों में निवेश के अवसरों, विस्तार योजनाओं एवं रणनीतिक साझेदारियों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। साथ ही, गुजरात के मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, निवेशक-अनुकूल नीतियों तथा सतत एवं प्रौद्योगिकी-आधारित विकास के अगले चरण के लिए राज्य की तैयारियों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा।

वडोदरा मंडल में 29 अगस्त से 9 सितंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान

स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने तथा रेलवे स्टेशनों एवं परिसरों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं जनसहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन में 29 अगस्त से 09 सितंबर 2026 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, शपथ एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज वडोदरा स्थित स्टेशन, लोको शेड, मेमू शेड तथा उत्राण,

अंकलेश्वर, भरूच, विश्वामित्री, मियागाम करजन, नडियाद, आणंद, एकतानगर, अलीराजपुर, गोधरा सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में रेलकर्मियों, आरपीएफ एवं जीआरपी स्टाफ, यात्रिओं, कुलियों, वेंडरों तथा सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी ने अपने कार्यस्थल एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने, गंदगी न फैलाने तथा स्वच्छता के प्रति दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। अभियान के दौरान सभी को स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे अपनी दैनिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सभी को विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ रेलवे परिसरों को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतर बनाने में सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है।

विशेष स्वच्छता अभियान के तहत मंडल के स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों तथा सफाई कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान यात्रियों को रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, कचरे का उचित निस्तारण करने तथा रेलवे नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया।

वडोदरा मंडल द्वारा इस विशेष अभियान के माध्यम से "स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है" का संदेश दिया जा रहा है। मंडल ने सभी रेलकर्मियों, यात्रियों, वेंडरों, कुलियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता करने तथा स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ रेलवे परिसर के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की गयी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बहुचराजी में माँ बहुचर के चरणों में शीश झुकाकर सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार शाम सुप्रसिद्ध यात्राधाम और शक्तिपीठ बहुचराजी में माँ बहुचर के चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर दर्शन किए। मंदिर परिसर में शास्त्रोक्त विधि-विधान के साथ उन्होंने आद्यशक्ति की पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने माँ बहुचर के दर्शन कर सभी के सुख, शांति और समृद्धि के लिए अंतःकरणपूर्वक प्रार्थना की।

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

इस अवसर पर उनके साथ जिला प्रभारी मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, विधायक श्री सुखाजी ठाकोर सहित उपस्थित महानुभावों ने भी माँ आद्यशक्ति के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती शालिनी दुहान, जिला विकास अधिकारी श्री प्रदीपसिंह राठौड, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु सोलंकी व निवासी अपर कलेक्टर श्री मयंक पटेल भी उपस्थित रहे।

सावन में महाकाल के दरबार में टूटा आस्था का रिकॉर्ड, 30 दिन में 1.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष सावन माह के दौरान आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला। सावन के 30 दिनों में करीब 1 करोड़ 57 लाख 210 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना अपने आप में नया रिकॉर्ड है। देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। मंदिर परिसर से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक पूरे सावन धार्मिक वातावरण बना रहा और लगातार भक्तों की कतारें दिखाई देती रहीं।

मंदिर प्रबंध समिति के आंकड़ों के अनुसार सावन माह के दौरान 1 करोड़ 13 लाख 25 हजार 210 श्रद्धालुओं ने सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके अलावा करीब 43 लाख 75 हजार भक्तों ने बाबा महाकाल की सवारी तथा भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए। धार्मिक आयोजनों और सावन की विशेष परंपराओं के कारण उज्जैन में पूरे महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।

सावन हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की धार्मिक महत्ता के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्या विशेष रूप से अधिक रहती है। ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखने वाले बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु पहुंचे।

इस बार मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ दर्शन व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन और मंदिर समिति के सामने बड़ी चुनौती रही। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना, उन्हें सुरक्षित तरीके से मंदिर तक पहुंचाना और दर्शन के बाद बाहर निकालना आसान काम नहीं था। इसके बावजूद मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम किया।

बाबा महाकाल की सावन सवारी भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। परंपरा के अनुसार सावन के दौरान बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सवारी के दर्शन के लिए उज्जैन ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पूरे शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा।

भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन भी सावन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में विशेष अवसर पर ही दर्शन के लिए खोला जाता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर

के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल की सवारी और नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी इस वर्ष लाखों में रही।

श्रद्धालुओं की भारी संख्या का सीधा असर मंदिर की आय पर भी पड़ा। मंदिर समिति के अनुसार सावन माह के दौरान करीब 5 लाख 76 हजार 370 शीघ्र दर्शन टिकटों की बिक्री हुई। इन टिकटों से मंदिर समिति को लगभग 14 करोड़ 47 लाख 42 हजार 500 रुपये की आय हुई। यह आंकड़ा बताता है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मंदिर की व्यवस्थाओं और धार्मिक गतिविधियों के लिए मिलने वाले आर्थिक संसाधनों में भी वृद्धि हुई है।

बाबा महाकाल के दर्शन के साथ प्रसादी की मांग भी इस दौरान काफी बढ़ी। मंदिर में तैयार होने वाले लड्डू प्रसाद को श्रद्धालु बड़ी संख्या में खरीदते हैं। इस वर्ष सावन माह में करीब 2,215.939 क्विंटल लड्डू प्रसादी की बिक्री हुई। इससे मंदिर समिति को लगभग 10 करोड़ 49 लाख 27 हजार 250 रुपये की आय प्राप्त हुई। इतनी बड़ी मात्रा में प्रसादी की बिक्री श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की व्यवस्थाओं के विस्तार को भी दर्शाती है।

सावन के दौरान उज्जैन पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या भी काफी अधिक रही। मंदिर समिति के अनुसार पांच लाख से अधिक कांवड़िए बाबा महाकाल को जल अर्पित करने पहुंचे। कांवड़ियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उनके लिए अलग से जल अर्पण की व्यवस्था की गई थी, ताकि सामान्य दर्शन व्यवस्था प्रभावित न हो और कांवड़ यात्री भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत बाबा महाकाल को जल अर्पित कर सकें।

कांवड़ यात्रियों के जत्थे अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों से उज्जैन पहुंचे। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए मंदिर तक आए और भगवान शिव को जल अर्पित किया। सावन के पूरे महीने शहर में कांवड़ियों की आवाजाही बनी रही। उनके जयकारों से धार्मिक वातावरण और भी भक्तिमय हो गया।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में भोजन की व्यवस्था भी की गई। मंदिर के अन्न क्षेत्र में करीब 3 लाख 47 हजार 912 श्रद्धालुओं ने निशुल्क भोजन प्रसादी ग्रहण की। बड़ी संख्या में भक्तों को भोजन उपलब्ध कराना मंदिर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण सेवा कार्य रहा। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऐसी व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी रही।

भीड़ के दौरान कई श्रद्धालुओं के जूते-चप्पल भी गुम हो गए। मंदिर समिति ने ऐसे श्रद्धालुओं के लिए चरण पादुका की व्यवस्था की। आंकड़ों के अनुसार 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को निशुल्क चरण पादुका उपलब्ध कराई गई। इससे पता चलता है कि मंदिर प्रशासन ने केवल दर्शन व्यवस्था ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की छोटी-बड़ी जरूरतों पर भी ध्यान दिया।

सावन के दौरान उज्जैन शहर की अर्थव्यवस्था पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ का व्यापक असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के कारण होटल, धर्मशाला, परिवहन, भोजनालय, फूल-माला, धार्मिक सामग्री और स्थानीय बाजारों में गतिविधियां बढ़ीं। दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए सावन का महीना कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण उज्जैन में परिवहन व्यवस्था पर भी दबाव रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही रही। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अलग-अलग स्तर पर व्यवस्थाएं कीं।

महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। मंदिर के प्रति देशभर के लोगों की आस्था के साथ-साथ उज्जैन में विकसित हो रही सुविधाओं ने भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। महाकाल लोक के विकास के बाद उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मंदिर क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में बेहतर व्यवस्था मिलने लगी है।

इस वर्ष के आंकड़ों ने पिछले कई रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। वर्ष 2023 में सावन-भादो के दौरान करीब 99 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे थे। वर्ष 2024 में यह संख्या लगभग 90 लाख रही थी। वर्ष 2025 में करीब 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। लेकिन इस वर्ष केवल सावन के 30 दिनों में ही 1 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से नया रिकॉर्ड कायम हो गया।

श्रद्धालुओं की संख्या में यह वृद्धि मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाती है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में उज्जैन की पहचान पहले से ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां धार्मिक पर्यटन का विस्तार तेजी से हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ श्रद्धालु महाकाल लोक, काल भैरव, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का भी रुख करते हैं।

सावन के दौरान बाबा महाकाल की भस्म आरती और विशेष पूजन का भी विशेष महत्व रहा।

अफगानिस्तान में बिछेगा रेल संपर्क का नया जाल, 1,537 किमी नई रेलवे लाइन की तैयारी; क्षेत्रीय व्यापार को मिलेगी रफ्तार

काबुल। अफगानिस्तान ने अपने रेल नेटवर्क को विस्तार देने और देश को क्षेत्रीय व्यापार के बड़े मार्गों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश में पांच प्रमुख रेल मार्गों पर कुल 1,537 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय के अनुसार, इन प्रस्तावित रेल परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और डिजाइन का काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद अफगानिस्तान की माल ढुलाई क्षमता बढ़ने के साथ देश के मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बाजारों से संपर्क को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय के अनुसार जिन प्रमुख मार्गों को नई रेलवे परियोजनाओं में शामिल किया गया है, उनमें तोरघुंडी-हेरात, हेरात-कंधार, कंधार-स्पिन बोल्दाक, काबुल-कंधार और अंदखोय-शेबेरघान मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों को अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और भविष्य के व्यापारिक संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित रेल नेटवर्क देश के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों को आपस में जोड़ने के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ संपर्क मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है।

अफगानिस्तान लंबे समय से परिवहन और संपर्क की कमजोर व्यवस्था से जूझता रहा है। देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां सड़क मार्ग से लंबी दूरी तक माल ढुलाई में समय और लागत दोनों अधिक हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन ढांचे का विकास भी चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क का विस्तार अफगानिस्तान के लिए केवल परिवहन परियोजना नहीं बल्कि आर्थिक विकास और क्षेत्रीय व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान के सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय के मुताबिक नई परियोजनाओं के लिए घरेलू वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों, विभिन्न देशों और संभावित निवेशकों से भी बातचीत की जा रही है। इतनी बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी और सरकार अकेले अपने संसाधनों से इसका पूरा वित्तपोषण करने की स्थिति में नहीं हो सकती। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, निजी निवेश और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। नई रेल लाइनों के निर्माण से अफगानिस्तान में माल ढुलाई की लागत कम होने की उम्मीद है। भारी मात्रा में माल को लंबी दूरी तक सड़क के बजाय रेल से ले जाने पर परिवहन अधिक व्यवस्थित और अपेक्षाकृत किफायती हो सकता है। इससे कृषि उत्पाद, खनिज, निर्माण सामग्री और अन्य व्यापारिक वस्तुओं को देश के विभिन्न हिस्सों तथा सीमा पार बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिल सकती है।

रेल नेटवर्क का विस्तार अफगानिस्तान के लिए पारगमन व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच स्थित अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे क्षेत्रीय व्यापार के लिए संभावित संपर्क केंद्र बनाती है। यदि देश में पर्याप्त रेल और सड़क संपर्क विकसित होता है तो पड़ोसी देशों के बीच माल की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभर सकता है।

नेपाल की बाढ़ में भारत की मदद की गूंज, शशि थरूर ने मोदी सरकार की कार्रवाई को सराहा; बोले- राहत अभियान और तेज करने की जरूरत

नई दिल्ली। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और उससे पैदा हुए संकट के बीच भारत की ओर से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सराहना की है। थरूर ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर कहा कि नेपाल में प्राकृतिक आपदा के बाद भारत की प्रतिक्रिया तेज, प्रभावी और मानवीय रही है। उन्होंने कहा कि संकट की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू से तत्काल संपर्क स्थापित किया और नेपाल को राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता तथा बचाव विशेषज्ञों की मदद उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम उठाए।

थरूर ने अपने पत्र में कहा कि पड़ोसी देश नेपाल के सामने इस समय गंभीर मानवीय संकट है और ऐसे समय में भारत की सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच केवल कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते भी हैं। प्राकृतिक आपदा के समय एक-दूसरे की

मदद करना इन संबंधों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।

कांग्रेस सांसद ने नेपाल के त्रिशुली-1 क्षेत्र में फंसे भारतीय मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने को राहत अभियान की महत्वपूर्ण सफलता बताया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना बड़ी उपलब्धि है और इससे प्रभावित परिवारों को काफी राहत मिली है। थरूर के मुताबिक इन मजदूरों के परिवारों ने भारत की ओर से किए गए प्रयासों के लिए आभार भी जताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बचाव अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और नेपाल के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग अब भी मुश्किल परिस्थितियों में फंसे हो सकते हैं। ऐसे में राहत और बचाव अभियान को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में हर गुजरता घंटा महत्वपूर्ण होता है और समय बीतने के साथ मलबे या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है। थरूर ने विदेश मंत्री को लिखे पत्र में सुझाव दिया कि भारत को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की पूरी टीम और आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणों को नेपाल भेजने पर तत्काल विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खोज और बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों के साथ आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए आधुनिक खोज उपकरणों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। प्राकृतिक आपदा के दौरान इमारतों और अन्य ढांचों के गिरने से लोग भारी मलबे के नीचे दब सकते हैं।

ऐसे मामलों में सामान्य बचाव उपकरणों के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जीवन बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। थरूर का कहना है कि उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित जीवित व्यक्ति तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। कांग्रेस सांसद ने नेपाल के पासांग ल्हामू राजमार्ग को खोलने के लिए भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स की मदद लेने का भी सुझाव दिया। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं, जिससे राहत सामग्री और बचाव दल प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सड़क संपर्क बहाल करना राहत अभियान की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल हो जाता है। थरूर के मुताबिक यदि सेना की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर बाधित मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाता है तो दूरदराज के इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाना आसान हो सकता है। सड़कें बहाल होने से न केवल राहत दलों की आवाजाही तेज होगी, बल्कि भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी।

उन्होंने दूरदराज के और दुर्गम क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के भारी हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया। नेपाल का भौगोलिक क्षेत्र कई जगह पहाड़ी और दुर्गम है। बाढ़, भूस्खलन या सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में कई इलाकों तक सड़क मार्ग से पहुंचना कठिन हो सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाना और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालना अधिक प्रभावी विकल्प हो सकता है।

थरूर ने कहा कि राहत अभियान में प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए जहां सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है या जहां बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत के आधार पर किया जाए और नेपाल सरकार के साथ समन्वय बनाकर राहत अभियान को आगे बढ़ाया जाए।

30 अगस्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस

गुजरात में एमएसएमई को ऋण वितरण में भारी इजाफा : बैंकों ने वर्ष 2025-26 में 3.79 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए, लक्ष्य का 122% हासिल हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर की भूमिका अहम होगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य सरकार के गहन प्रयासों के साथ बैंकिंग सेक्टर का सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात (एसएलबीसी) के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए निर्धारित 3,10,917 करोड़ रुपए के ऋण लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 3,79,535 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर 122.07 फीसदी सफलता की उपलब्धि हासिल की है। इस प्रकार, एमएसएमई इकाइयों को 68,618 करोड़ रुपए अधिक ऋण वितरित किया गया है, जो राज्य के औद्योगिक सिस्टम में मजबूत विश्वास का संकेत देता है। भारत में प्रतिवर्ष 30 अगस्त को 'राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस' मनाया जाता है, जो लघु उद्योगों के महत्व और देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को उजागर करता है।

गुजरात में 33 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां

गुजरात देश के अग्रणी एमएसएमई राज्यों में से एक है। राज्य में 33 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। एमएसएमई के लिए 122.07 फीसदी के ऋण लक्ष्य की उपलब्धि केवल बैंकिंग क्षेत्र की ही उपलब्धि नहीं, बल्कि गुजरात के छोटे और मझौले उद्योगों में बढ़ती वित्तीय पहुंच और राज्य के उद्यमशील माहौल की मजबूती का भी प्रतिबिंब है। सुव्यवस्थित बैंकिंग सपोर्ट और विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों के साथ गुजरात का एमएसएमई क्षेत्र निवेश, उद्यमशीलता, रोजगार और औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन रहा है।

एमएसएमई को ऋण देने के लिए डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यावसायिक ऋण प्रदान करने के लिए एक नई कंप्यूटर-आधारित प्रणाली का उपयोग शुरू किया है, जिसे 'क्रेडिट एसेसमेंट मॉडल' कहा जाता है। यह प्रणाली केवल कागजी कार्यवाही और मैन्युअल जांच पर निर्भर रहने के बजाय व्यवसाय के 'डिजिटल फुटप्रिंट' यानी टैक्स फाइलिंग और बैंक रिकॉर्ड्स जैसी व्यवसाय की ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए काम करता है।

यह प्रक्रिया कैसे काम करती है?

इस प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम स्वतः ही ऐसी जानकारियां हासिल कर लेता है, जो पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं- जैसे केवाईसी, फोन नंबर और ईमेल, जीएसटी फाइलिंग का ब्योरा, बैंक स्टेटमेंट का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापन, इनकम टैक्स रिटर्न, क्रेडिट हिस्ट्री और अन्य आवश्यक जानकारियां जो क्रेडिट यानी ऋण देने के लिए आवश्यक हैं। इन सभी जानकारियों का उपयोग करके सिस्टम यह तय करता है कि किसी व्यवसाय को कितना ऋण दिया जा सकता है।

फोन या कंप्यूटर से आवेदन करने की व्यवस्था

ऋण लेने के लिए फोन या कंप्यूटर से आवेदन किया जा सकता है, इसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम कागजी कार्यवाही की जरूरत होती है, इसलिए समय की बचत होती है। अक्सर तुरंत ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाती है। आवेदन करने से लेकर मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। ऋण देने का निर्णय व्यवसाय के विवरण जैसे आय और खर्च और ऋण चुकौती रिकॉर्ड जैसे डेटा के आधार पर लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) जैसी सरकारी योजनाएं पहले से ही सिस्टम में एकीकृत होती हैं, जिससे बहुत से छोटे व्यवसायों को संपत्ति या अन्य किसी मालसामान या परिसंपत्ति को गिरवी रखे बिना ही ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर की भूमिका अहम होगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर में हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 190वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर की भूमिका अहम होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बैंकिंग सेक्टर को अपनी सेवाओं के जरिए 'क्रेडिट टू लास्ट माइल' की अवधारणा को साकार करते हुए एमएसएमई, महिला उद्यमियों, ग्रामीण कारीगरों और छोटे किसानों सहित समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम लोगों तक आसानी से ऋण पहुंचाने का आह्वान किया।

पश्चिम रेलवे द्वारा तीन जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का साबरमती के स्थान पर गांधीग्राम स्टेशन से संचालन प्रारंभ,यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं रेल सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार साबरमती स्टेशन से प्रारंभ एवं समाप्त होने वाली तीन जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का टर्मिनल अब गांधीग्राम स्टेशन कर दिया गया है। इन ट्रेनों का गांधीग्राम स्टेशन से निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालन प्रारंभ हो चुका है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गांधीग्राम स्टेशन से इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधा एवं सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है—

1. ट्रेन संख्या 14822/14821 गांधीग्राम–जोधपुर–गांधीग्राम दैनिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 14822 गांधीग्राम–जोधपुर दैनिक एक्सप्रेस प्रतिदिन गांधीग्राम स्टेशन से सुबह 07.00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन शाम 18.10 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर–गांधीग्राम दैनिक एक्सप्रेस प्रतिदिन जोधपुर से सुबह 10.00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात्रि 21.00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

2. ट्रेन संख्या 12548/12547 गांधीग्राम–आगरा कैंट–गांधीग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12548 गांधीग्राम–आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन—सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार—गांधीग्राम स्टेशन से शाम 16.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 07.05 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 12547 आगरा कैंट–गांधीग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन—सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार—आगरा कैंट से रात्रि 22.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12.00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

3. ट्रेन संख्या 22548/22547 गांधीग्राम–ग्वालियर–गांधीग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22548 गांधीग्राम–ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन—मंगलवार, शुक्रवार एवं शनिवार—गांधीग्राम स्टेशन से शाम 16.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 09.25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 22547 ग्वालियर–गांधीग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन—बुधवार, शनिवार एवं रविवार—ग्वालियर से रात्रि 20.10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12.00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर मंडल, श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पूर्व राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES), यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) तथा रेलवे के अधिकृत सूचना माध्यमों से ट्रेन के अद्यतन समय, ठहराव एवं संचालन संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि यात्रा अधिक सुविधाजनक एवं सुगम हो सके।

पश्चिम रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुविधाजनक एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सोमनाथ दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे ने दो जोड़ी ट्रेनों में लगाया अतिरिक्त जनरल कोच,श्रावण माह के दौरान 01 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी अतिरिक्त यात्री क्षमता

श्रावण माह के दौरान सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा महत्वपूर्ण यात्री सुविधा प्रदान की जा रही है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भावनगर मंडल से होकर संचालित होने वाली दो जोड़ी दैनिक यात्री ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री क्षमता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित ट्रेनों में 01 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 तक एक-एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जाएगा:

- ट्रेन संख्या 19120/19119 वेरावल–गांधीनगर कैपिटल–वेरावल दैनिक एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 59558/59559 भावनगर–वेरावल–भावनगर दैनिक पैसेन्जर

इस अतिरिक्त कोच की सुविधा से श्रावण माह के दौरान सोमनाथ दर्शन के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं एवं अन्य यात्रियों को अधिक सीटिंग क्षमता और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। पश्चिम रेलवे यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुरूप यात्री सुविधाओं में निरंतर वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से इस अतिरिक्त सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपनी यात्रा को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है।

पश्चिम रेलवे द्वारा श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रावण माह के दौरान सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

यात्रियों की बढ़ती मांग एवं अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने तीन जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरों का किया विस्तार

यात्रियों की बढ़ती मांग, यात्रा सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने भावनगर मंडल से होकर संचालित तीन जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से यात्रियों को आगामी अवधि में भी सुगम एवं सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिलता रहेगा।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार विस्तारित फेरों का विवरण निम्नानुसार है—

1. भावनगर टर्मिनस–बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल (09208/09207)

ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस–बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल का संचालन अब 26 नवंबर, 2026 तक किया जाएगा। इससे पूर्व यह ट्रेन 27 अगस्त, 2026 तक अधिसूचित थी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09207 बान्द्रा टर्मिनस–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल अब 27 नवंबर, 2026 तक संचालित होगी, जबकि पहले इसका संचालन 28 अगस्त, 2026 तक निर्धारित था।

2. वेरावल–हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल (09203/09204)

ट्रेन संख्या 09203 वेरावल–हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल का संचालन 20 अक्टूबर, 2026 से 24 नवंबर, 2026 तक किया जाएगा। पूर्व में यह ट्रेन 28 जुलाई, 2026 तक अधिसूचित थी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09204 हरिद्वार–वेरावल साप्ताहिक स्पेशल अब 21 अक्टूबर, 2026 से 25 नवंबर, 2026 तक संचालित होगी, जबकि पहले इसका संचालन 29 जुलाई, 2026 तक निर्धारित था।

3. भावनगर टर्मिनस-शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल (09257/09258)

ट्रेन संख्या 09257 भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल का संचालन 16 अक्टूबर, 2026 से 27 नवंबर, 2026 तक किया जाएगा। पूर्व में यह ट्रेन 31 जुलाई, 2026 तक अधिसूचित थी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09258 शकूर बस्ती–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल अब 17 अक्टूबर, 2026 से 28 नवंबर, 2026 तक संचालित होगी, जबकि पहले इसका संचालन 01 अगस्त, 2026 तक निर्धारित था।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम रेलवे का यह निर्णय यात्रियों की सुविधा, बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने तथा त्योहार एवं अवकाश अवधि के दौरान अतिरिक्त भीड़ के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपरोक्त सभी आरक्षित ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग 01 सितंबर, 2026 (मंगलवार) से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना की अद्यतन जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा एनटीईएस (NTES) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 27 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09208 भावनगर टर्मिनस–बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 26 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09033 उधना–मालदा टाउन साप्ताहिक स्पेशल को 26 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09034 मालदा टाउन–उधना साप्ताहिक स्पेशल को 29 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09033 उधना–मालदा टाउन साप्ताहिक स्पेशल 24 सितम्बर तथा 1 अक्टूबर, 2026 को नहीं चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09034 मालदा टाउन–उधना साप्ताहिक स्पेशल 27 सितम्बर तथा 4 अक्टूबर, 2026 को नहीं चलेगी।
3. ट्रेन संख्या 09065 सूरत–छपरा साप्ताहिक स्पेशल के फेरों को 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09066 छपरा–सूरत साप्ताहिक स्पेशल के फेरों को 21 अक्टूबर से 18 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09119 प्रतापनगर–लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल को 29 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09120 लालकुआं–प्रतापनगर साप्ताहिक स्पेशल को 30 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09195 प्रतापनगर–मऊ साप्ताहिक स्पेशल को 28 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09196 मऊ–प्रतापनगर साप्ताहिक स्पेशल को 29 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद–मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल को 27 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09423 मंगलुरु–अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल को 28 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
7. ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम–भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल को 27 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर–गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल को 30 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
8. ट्रेन संख्या 09425 साबरमती–हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल को 19 अक्टूबर से 23 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार–साबरमती साप्ताहिक स्पेशल को 20 अक्टूबर से 24 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
9. ट्रेन संख्या 09523 ओखा–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल को 20 अक्टूबर से 24 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09524 शकूर बस्ती–ओखा साप्ताहिक स्पेशल को 21 अक्टूबर से 25 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
10. ट्रेन संख्या 09203 वेरावल–हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल को 20 अक्टूबर से 24 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09204 हरिद्वार–वेरावल साप्ताहिक स्पेशल को 21 अक्टूबर से 25 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
11. ट्रेन संख्या 09257 भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल को 16 अक्टूबर से 27 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09258 शकूर बस्ती–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 17 अक्टूबर से 28 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
12. ट्रेन संख्या 09309 इंदौर–हज़रत निज़ामुद्दीन द्विसाप्ताहिक स्पेशल को 27 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09310 हज़रत निज़ामुद्दीन–इंदौर द्विसाप्ताहिक स्पेशल को 28 नवम्बर, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09207, 09208, 09033, 09065, 09119, 09195, 09424, 09451, 09425, 09523, 09203, 09257 तथा 09309 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01.09.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कछुओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल : गुजरात के मछुआरे पहली बार अपनाएंगे 'टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस'

गांधीनगर : देश में सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात मत्स्यपालन क्षेत्र में हमेशा से एक अग्रणी राज्य रहा है। मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शुरू की गई 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के अंतर्गत समुद्री जीवसृष्टि के संरक्षण और सी-फूड (समुद्री भोजन) निर्यात क्षेत्र को नई वैश्विक पहचान देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार गुजरात में पहली बार मछुआरों की फिशिंग नेट में 'टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस' (टीईडी) लगाने की पहल शुरू करने जा रही है।

मत्स्योद्योग मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के 8925 मछुआरों को सौ फीसदी सरकारी सहायता के साथ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस मुफ्त में दी जाएगी। 20.96 करोड़ रुपए के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से समुद्री जीवसृष्टि के संरक्षण के साथ-साथ गुजरात के सीफूड उद्योग के लिए वैश्विक बाजारों के और द्वार खुलेंगे।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका ने भारतीय 'वाइल्ड कॉट श्रिम्प' यानी समुद्र से पकड़े गए झींगों के आयात पर अंकुश लगा दिया है, जिसकी मुख्य वजह मछली पकड़ने के दौरान समुद्री कछुओं के जाल में फंसकर घायल होने का खतरा था। अब टीईडी के उपयोग से कछुओं के लिए खतरा कम हो जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के आवश्यक सर्टिफिकेशन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नतीजतन, अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गुजरात के झींगे का निर्यात फिर से बढ़ जाएगा, जिससे राज्य के मछुआरों और सीफूड निर्यातकों की आय में भारी बढ़ोतरी होगी।

भारत सरकार ने देशभर में सर्वाधिक 8925 टीईडी यूनिट अकेले गुजरात के लिए मंजूर किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी (सीआईएफटी), कोची ने यूएस-नेशनल ओशिएनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के विनिर्देशों के अनुरूप टीईडी का यह विशिष्ट मॉडल विकसित किया है।

बता दें कि टीईडी झींगा पकड़ने वाले ट्रॉल नेट (जाल) में लगाया जाने वाला एक विशिष्ट उपकरण है, जो झींगे को तो जाल में फंसा रहने देता है, लेकिन कछुए जैसे बड़े समुद्री जीवों को 'एग्जिट फ्लैप' के जरिए बाहर निकलने का रास्ता देता है। इससे कछुए की मृत्युदर में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी।

पर्यावरणीय संतुलन और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को कवर करने वाला यह अभिनव प्रयास मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और मत्स्यपालन मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी के ईमानदार प्रयासों से गुजरात की 'ब्लू इकोनॉमी' को वैश्विक फलक पर एक नई ऊंचाई देगा।

अमेरिका में गुजरातियों की सुरक्षा पर सवाल: डेढ़ साल में पांच हत्याओं ने परिवारों में चिंता पैदा कर दी है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

अमेरिका में रहने वाले गुजरातियों की बार-बार हत्या क्यों हो रही है? चार दिन पहले न्यूयॉर्क शहर में घटी एक घटना में, पंजाब के कपूरथला निवासी 28 वर्षीय गुरदीप सिंह को पिज्जा डिलीवरी के लिए जाते समय अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह पिछले 13 वर्षों से अमेरिका में रह रहे थे और वहीं से अपनी आजीविका कमा रहे थे।

अपराधियों को मेहसाना के 62 वर्षीय पटेल की हत्या से नकदी भी मिली, जबकि गुरदीप सिंह को गोली मारने वाले को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने गोलियां चलाईं क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों में भय फैलाना था। जैक्सन सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब 62 वर्षीय पिता सुरेश पुरुषोत्तम दास की उनकी 19 वर्षीय बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर

दी गई। इतना ही नहीं, नकाबपोश लुटेरे को नकदी ले जाने देने के बावजूद उसने लूटपाट की और अंधाधुंध गोलीबारी की। सुरेश पटेल मूल रूप से मेहसाना जिले के आखज गांव के रहने वाले थे। पिछले साल मई 2025 में, आनंद के 30 वर्षीय परेश पटेल, जिन्हें प्रिंस पटेल के नाम से भी जाना जाता था, को गोली मार दी गई थी। दो महीने पहले वर्जीनिया में 45 वर्षीय मेघना पटेल की हत्या करने वाले बंदूकधारियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। सितंबर 2025 में, मूल रूप से चारोतर के रहने वाले किरण पटेल एक लुटेरे का सामना करते हुए शहीद हो गए। अमेरिका में सशस्त्र लुटेरों के पीड़ितों की सूची लंबी है। लेकिन हमलावर शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। ये अपराधी या तो बेरोजगार हैं या नशे के आदी हैं।

इस प्रकार, डेढ़ साल में पांच गुजरातियों की हत्या ने अमेरिका में रहने वाले गुजराती परिवारों में चिंता की लहर फैला दी है। किराने की दुकानें चलाने वाले, पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले, शराब की दुकानों और मोटलों में काम करने वाले गुजराती हमलावरों का शिकार बन रहे हैं। कई गुजरातियों के साथ-साथ, किराने की दुकानें और मोटल उद्योग भी गुजरातियों के स्वामित्व में हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत गुजराती हैं। अमेरिका में रहने वाले गुजराती प्रभावशाली हैं और राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार, अमेरिका में रहने वाले गुजराती समृद्ध हैं। इसलिए, गुजराती हमलावरों के निशाने पर आ गए हैं। तो भारतीयों की सुरक्षा का क्या होगा?